the Expert Committee.

भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी हेतु कराया गया अध्ययन

1577. **श्री अजीत जोगी:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी हेतु कराये गये अध्ययन में यह सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के वर्गीकरण संबंधी नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त प्रतिवेदन को जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त प्रतिवेदन की सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ङ) आयकर अधिनियम की धारा 80-1क के तहत कर अवकाश प्रदान करने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का वर्गीकरण तथा पहचान करने के लिए वित्त मंत्रालय में एक अध्ययन समूह गठित किया गया था। अध्ययन समूह ने अक्टूबर, 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनेक राज्यों ने सुझाव दिया था कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए जिले के बजाय, तालुक या तहसील को अधिसूचना के लिए आधार एकक के रूप में लिया जाना चाहिए। कुछ अन्य मुद्दों के अलावा इस मामले की जांच करने के लिए, वित्तमंत्रालय में एक समीक्षा अध्ययन समूह का गठन किया गया था। समीक्षा अध्ययन समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो देश के ओद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों/तालुकों को अधिसूचित करने के लिए सरकार के विचाराधीन है।

Rehabilitation of loss making Public Sector Enterprises

1578. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to wind up those public sector enterprises which cannot stand up on their feet and are in red inspite of rehabilitation help having been provided to them;

(b) if so, whether Government have prepared a list of loss making P.S.Es;

(c) if so, the details of the same; and

(d) the steps proposed to be taken to provide alternative employment to the employees of enterprises facing closure?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) No, Sir.

(b) to (d) do not arise.

Role of Multinationals in Development

1579. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the role of multinational companies in country's economic development, especially development of backward areas and creation of employment;

(b) whether Government propose to discourage entry of multinational companies into low priority areas especially consumer goods sector; and

(c) if so, steps taken so far in this regard?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) The promotion of foreign direct Investment (FDI) is an important corner-stone of the major programme of economic reforms which seeks to move India rapidly into the global economy, make Indian industry internationally competitive, ensure optimal utilisation of human resources and transform India into a major partner of the developed and developing nations. Foreign investment including FDI from MNCs would bring